एस.एम.एस. अस्पताल में किशोरी के पेट से निकाला दुनिया का सबसे लंबा ट्राइकोबेज़ोआर

210 सेंटीमीटर लंबा बालों का गोला, अब तक का विश्व रिकॉर्ड

जयपुर। राजस्थान के सबसे बडे सवाई मानसिंह अस्पताल के चिकित्सकों ने चिकित्सा क्षेत्र में एक अनोखा कीर्तिमान स्थापित किया है। आगरा उत्तर प्रदेश के बरारा गांव की एक 14 वर्षीय किशोरी के पेट से 210 सेंटीमीटर लंबा ट्राइकोबेज़ोआर (बालों का गोला) निकाला गया। जो अब तक का दुनिया का सबसे लंबा ट्राइकोबेज़ोआर बताया जा रहा है। इससे पहले का रिकॉर्ड 180 सेंटीमीटर का था।

एसएमएस अस्पताल के जनरल सर्जरी विभाग के सीनियर प्रोफेसर डॉ. जीवन कांकरिया ने बताया कि किशोरी कक्षा 10 की छात्रा है और वह मिट्टी, चॉक, लकड़ी और धागे खाने की आदत, जिसे मानसिक विकार पिका कहते हैं, से ग्रसित थी। यह आदत उसने कक्षा 6 से शुरू की थी, जो धीरे-धीरे गंभीर होती गई। किशोरी पिछले एक महीने से पेट दर्द और उल्टी की शिकायत के चलते इलाज करा रही थी। जांच में पेट से नाभि तक फैली एक सख्त गांठ पाई गई। सीईसीटी स्कैन से पता चला कि पेट में असामान्य वस्तु मौजूद है।

ऑपरेशन करने वाली एस.एम.एस. के चिकित्सक डॉ. जीवन कांकरिया और टीम।

लैपरोटॉमी सर्जरी के दौरान चिकित्सक यह देखकर हैरान रह गए कि बालों का यह गोला केवल पेट तक सीमित नहीं था, बल्कि छोटी आंत के डिस्टल इलियम तक फैला हुआ था। सर्जरी लगभग दो घंटे चली और इसमें खून चढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। डॉक्टरों ने इसे एक ही टुकड़े में निकालने में सफलता पाई, जिससे आंतों में अतिरिक्त चीरे लगाने से बचा जा सका।

डॉ. कांकरिया ने कहा कि यह केस रिकॉर्ड बुक में दर्ज किया जाएगा क्योंकि यह न केवल लंबाई में सबसे बड़ा ट्राइकोबेज़ोआर है, बल्कि इसे सुरक्षित निकालना चिकित्सा कौशल की एक मिसाल है। सर्जरी के बाद मरीज की हालत स्थिर है और वह तेजी से स्वस्थ हो रही है। इस दुर्लभ और जटिल सर्जरी को एसएमएस अस्पताल के जनरल सर्जरी विभाग के सीनियर प्रोफेसर डॉ. जीवन कांकरिया और उनकी टीम ने अंजाम दिया। ऑपरेशन में डॉ. राजेन्द्र बुगालिया, डॉ. देवेंद्र सैनी, डॉ. अमित, और एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉ. सुनील चौहान सहित कई चिकित्सा विशेषज्ञ शामिल रहे।

महाराणा प्रताप की शौर्य गाथाएं हर दिल में भरती हैं ऊर्जा : दिया कुमारी

महाराणा प्रताप की 485वीं जयंती पर जयपुर के झोटवाड़ा में आयोजित समारोह में उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की।

जयपुर। वीरता, आत्मसम्मान और त्याग के प्रतीक महाराणा प्रताप की 485वीं जयंती पर जयपुर के झोटवाड़ा में आयोजित भव्य समारोह में उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप संस्था द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को देशभक्ति और शौर्य के वास्तविक अर्थ से परिचित कराना था।

दीया कुमारी ने अपने संबोधन में कहा, महाराणा प्रताप का जीवन साहस, स्वाभिमान और बलिदान की मिसाल है। उनका संघर्ष हमें यह सिखाता है कि न्याय और आत्मगौरव के लिए किसी भी परिस्थिति में डटे रहना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि हल्दीघाटी जैसे ऐतिहासिक स्थलों पर कुछ भ्रामक तथ्यों वाले शिलालेख लगाए गए थे, जिनमें महाराणा प्रताप को पराजित बताया गया था। बतौर सांसद रहते हुए उन्होंने इन शिलालेखों को हटवाकर सही ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर नए शिलालेख स्थापित करवाए। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि उनके प्रयासों से मेवाड़ क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं स्वीकृत हुईं, जिनमें महाराणा प्रताप सर्किट और स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना शामिल है। यह पहल न केवल क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का काम करेगी, बल्कि युवाओं में गौरव और प्रेरणा का संचार भी करेगी। कार्यक्रम की मुख्य आकर्षण रही वीरता की गायन प्रस्तुति ने उपस्थित जनसमूह में देशभक्ति की लहर जगा दी। समारोह में मौजूद लोगों ने महाराणा प्रताप के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। दीया कुमारी ने कार्यक्रम के समापन पर कहा, महाराणा प्रताप की शौर्य गाथाएं आज भी हमारे दिलों में नई ऊर्जा भरती हैं। यह आयोजन न केवल उन्हें श्रद्धांजलि देने का माध्यम है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को उनकी प्रेरणा से जोड़ने का भी एक सशक्त प्रयास है।

इस मौके पर महाराणा प्रताप जयंती कार्यक्रम में श्री श्री 1008 जगत जी महाराज, श्रवण सिंह बगड़ी, राजेन्द्र सिंह सिसोदिया, बर्दी सिंह राजावत विक्रम सिंह मुंडोता दिलीप सिंह सगवाड़, महेन्द्र कंवर, देवेंद्र कंवर, सीमा कंवर एवं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप संस्थान झोटवाड़ा के सदस्यगण एवं सम्माननीय समाजबंधु उपस्थित रहे।

रीको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना के द्वितीय चरण में भी दिखा निवेशकों का उत्साह

- 464 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए, ई-लॉटरी 5 जून को

जयपुर। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट-2024 में निवेशकों के साथ निष्पादित हुए एमओयू को धरातल पर उतारने के लिये राज्य सरकार पूर्ण रूप से कटिबद्ध है। निवेशकों को औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक भूखण्ड उपलब्ध कराने के लिए रीको ने प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 माह मार्च में प्रारंभ की, जिसे निवेशकों का भरपूर प्रोत्साहन मिला। माह मार्च-2025 में प्रारंभ हुए प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 के प्रथम चरण में निवेशकों का अत्यधिक उत्साह देखा गया जिसके पश्चात् मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान इंपेक्ट 1.0 के कार्यक्रम में इस योजना के समय विस्तार की घोषणा करते हुए कहा कि जो निवेशक 30 अप्रैल तक राज्य सरकार के साथ एमओयू निष्पादित करेंगे वह भी इस योजना में भूखण्ड आवंटन हेतु पात्र होंगे। एमओयू करने वाले उद्यमियों की रूचि को देखते हुए रीको ने इस योजना के द्वितीय चरण में 98 विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में करीब 7100 भूखण्ड आवंटन हेतु उपलब्ध करवाये। योजना में विभिन्न श्रेणियों/वर्गों के लिए भी भूखण्ड आरक्षित किये गये हैं जिनमें से अनूसूचित जाति/जनजाति के लिये 253, महिला वर्ग के लिये 224, भूतपूर्व सैनिकों के लिये 118, बेंचमार्क दिव्यांगता के लिये 151 तथा सशस्त्र बलों/अर्ध सैनिक बलों के मृतक आश्रित के लिये 62 भूखण्ड हैं। करीब 6300 भूखण्ड अनारक्षित हैं।

इस योजना में 15 से 28 मई तक ऑनलाइन आवेदन माँगे गये। रीको को आवेदन की अंतिम तिथि तक 464 आवेदन प्राप्त हुये हैं। औद्योगिक भूखण्डों के लिये इतनी अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होना निवेशकों का राज्य सरकार की नीतियों पर पूरा भरोसा दर्शाता है। प्रत्यक्ष आवंटन योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत निवेशकों को 88 औद्योगिक भूखण्डों का आवंटन कर दिया गया है।

प्रमुख शासन सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग एवं रीको अध्यक्ष अजिताभ शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार एमओयू को धरातल पर लाने के लिये भरपूर प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव एवं विभाग के स्तर पर एमओयू की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रत्यक्ष आवंटन योजना के द्वितीय चरण में रीको के 98 औद्योगिक क्षेत्रों में करीब 7100 भूखण्ड निवेशकों के लिये उपलब्ध कराये गये थे जिससे वे अपने उद्यम की आवश्यकता एवं रूचि के आधार पर सरलता से आरक्षित दर पर भूखण्ड प्राप्त कर सकें।

रीको प्रबंध निदेशक शिवांगी स्वर्णकार ने बताया कि योजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत 30 अप्रैल तक एमओयू निष्पादित करने वाले निवेशकों को भूखण्ड प्राप्त करने का अवसर दिया गया है। इसके अंतर्गत 464 आवेदन प्राप्त हुये हैं। जिन भूखण्डों पर एक ही आवेदन आया है, उनको डायरेक्ट ही ऑफर लेटर जारी कर दिया जायेगा तथा जिन भूखण्डों पर एक से ज्यादा आवेदन आये हैं, उनकी ई-लॉटरी 5 जून को निकाली जायेगी। तत्पश्चात् निवेशकों को तीन दिन में ही ऑफर लेटर जारी कर दिये जायेंगे, जिससे निवेशक अपनी औद्योगिक इकाई अतिशीघ्र प्रारंभ कर सकें।

नड्डा कल जयपुर आएंगे

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा 31 मई को जयपुर आएंगे। अहिल्याबाई होल्कर पर देश भर में आयोजित हुए कार्यक्रमों में राजस्थान दूसरे स्थान पर रहा, इसलिए जयपुर में बड़े स्तर पर आयोजन किया जा रहा है। यहां देवी अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में पार्टी की ओर से आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला के समापन समारोह में भाग लेंगे।

'उद्योगों को बदलती परिस्थितियों के अनुकूल ढलने और मिलकर समाधान खोजने की जरूरत है'

जयपुर। अनिश्चित और अप्रत्याशित वैश्विक परिस्थितियों ने अनुकूल उद्योगिक तरीके अपनाने और सहयोगात्मक समाधानों की महत्ता को जरूरी बना दिया है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए विचारों का आदान-प्रदान और संभावित रणनीतियों का निर्माण आज की आवश्यकता बन गया है। इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (राजस्थान) द्वारा आयोजित राउंडटेबल में "अपॉर्च्यूनिटीज इन द मिडस्ट ऑफ करंट ग्लोबल अनसर्टेनिटीज" विषय पर गहन चर्चा की गई। यह जानकारी आईसीसी राजस्थान चैप्टर की चेयरपर्सन, जयश्री पेरीवाल ने दी।

उन्होंने आगे बताया कि इस चर्चा की रूपरेखा आईसीसी मेबर्स रवि पोद्दार और मनुज गोयल ने तैयार की। उन्होंने यह भी कहा कि आईसीसी निर्णयकर्ताओं और पॉलिसी को प्रभावित करने वालों के बीच अर्थपूर्ण संवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

इस सत्र में राजेश जोशी, अमित भार्गव, रवि गोयनका, उदय परनामी, विज्ञान लोढ़ा और बृंदा रूंगटा ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। राउंडटेबल चर्चा का समापन जयकृष्ण जाजू के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह पहल विचारों के आदान-प्रदान के लिए मंच तैयार करने, नीतिगत बदलावों के साथ व्यावसायिक प्राथमिकताओं को संरेखित करने और राजस्थान के औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने की आईसीसी राजस्थान की निरंतर प्रतिबद्धता का हिस्सा है।

आईसीसी राजस्थान ने वैश्विक अनिश्चितताओं और उद्योग की प्रतिक्रिया पर राउंडटेबल का आयोजन किया।

इस वर्ष एलआईसी का लाभ 18.38 फीसदी अधिक रहा

जयपुर। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के निदेशक मंडल ने 31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिये स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों को मंजूरी दी और स्वीकृत किया।

31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिये कर के बाद लाभ 48151 करोड़ रुपये रहा, जबकि गत वर्ष से यह वृद्धि 18.38 फीसदी दर्ज की गई। निदेशक मंडल ने शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन वित्तीय वर्ष 24-25 के लिये प्रति शेयर 12 रुपये के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है।

31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिये कुल प्रीमियम आय 488148 करोड़ रुपये रही जो गत वर्ष को यह 475070 करोड़ रुपये थी। 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान व्यक्तिगत रुप से कुल 17782975 पॉलिसियां बेची गईं। गत वर्ष को समाप्त वर्ष के दौरान इन पॉलिसियों की संख्या 20392973 थी।

नये व्यवसाय का मूल्य 10011 करोड़ रुपये रहाप जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 4.47 फीसदी वृद्धि दर्ज की गई। शुद्ध वीएनबी मार्जिन 31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिये 80 बीपीएस से बढ़कर 17.6 फीसदी हो गया।

राज्य सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध 16 मामलों का निपटारा

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार एवं कदाचार के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए राज्य सेवा के अधिकारियों के विरूद्ध लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं अभियोजन स्वीकृति के 16 विचाराधीन प्रकरणों का निस्तारण किया है।

मुख्यमंत्री शर्मा ने भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अंतर्गत 5 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति प्रदान की तथा धारा 17-ए के एक प्रकरण में विस्तृत जांच एवं अनुसंधान की अनुमति प्रदान की है। इसी तरह कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न के प्रकरण में दोषी अधिकारी को सेवा से हटाया गया है। वहीं, पद के दुरूपयोग के साथ राज्य सरकार को वित्तीय हानि पहुंचाने की जांच के एक प्रकरण में आरोपित अधिकारी को राजकीय सेवा से बर्खास्त किया गया है। इसी तरह सेवानिवृत्त अधिकारियों के पुराने प्रकरणों का निस्तारण करते हुए 9 अधिकारियों की पेंशन रोके जाने की कार्यवाही की गई है तथा 5 सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के जांच निष्कर्ष का अनुमोदन भी किया गया है। इसके अतिरिक्त, सेवारत 3 अधिकारियों के विरूद्ध सीसीए नियम 16 के तहत 2 वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने का निर्णय किया गया है। वहीं, एक प्रकरण में प्रस्तुत अपील को खारिज करते हुए 17 सीसीए में प्रदत्त दंड को यथावत रखा गया है।

विश्व तंबाकू निषेध दिवस से पहले उठी सशक्त नीतियों की मांग

जयपुर। विश्व तंबाकू निषेध दिवस (31 मई) को लेकर राजस्थान तंबाकू मुक्त अलायंस की ओर से गुरुवार को जयपुर के एक निजी होटल में राज्य स्तरीय मीडिया आमुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य, सामाजिक जागरूकता और नीति निर्माण से जुड़े विशेषज्ञों ने भाग लिया और तंबाकू उद्योग के षड्यंत्रों को उजागर करने हेतु मीडिया की भूमिका को निर्णायक बताया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए अलायंस के अध्यक्ष डॉ. रमेश गांधी ने इस वर्ष की थीम "आकर्षण का पर्दाफाश करें। स्वाद, योजकों, विपणन रणनीतियों और धोखाधड़ीपूर्ण उत्पादों के माध्यम से तंबाकू उद्योग के षड्यंत्र को उजागर करें पर प्रकाश डाला।

राजस्थान में गुरुवार को कोविड के 15 नए केस आए सामने

- जयपुर सबसे अधिक प्रभावित, एम्स जोधपुर में 10 मरीज भर्ती

जयपुर। राजस्थान में एक बार फिर कोविड मामलों में हल्का उछाल देखने को मिला है। गुरुवार को प्रदेशभर से कुल 15 नए कोविड केस सामने आए हैं। जयपुर में सबसे अधिक 9 मामले मिले हैं, जबकि जोधपुर और उदयपुर से 2 और 4 संक्रमित पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 13 मरीज वर्तमान में विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। इनमें से 10 मरीज एम्स जोधपुर में, जबकि जेके लोन, ईएचसीसी और साकेत अस्पताल जयपुर में एक-एक मरीज उपचाराधीन हैं।

जानकारी के अनुसार कोविड के नए केस सबसे अधिक जयपुर में 9 नए केस सामने आए है। इनको मिलाकर अब तक 26 केस हो चुके है। इसी प्रकार राज्य के उदयपुर में 4 नए केस कुल 8, जोधपुर में 2 नए केस कुल 8, अन्य जिलों में अभी स्थिति स्थिर बनी हुई है। संक्रमितों की उम्र और प्रोफाइल की बात करें तो जोधपुर में 44 और 35 वर्षीय दो महिलाएं, उदयपुर में 29 व 59 वर्षीय पुरुष, 31 व 32 वर्षीय महिलाएं और जयपुर में 28 केस है, जिनमें संक्रमित 34, 34, 35, 21 वर्षीय पुरुष व 17, 55, 68, 71 वर्षीय महिलाएं शामिल है। अब तक का आंकड़ों की बात की जाएं तो 2025 में कुल केसों की संख्या 54 पहुंच चुकी है जिसमें अभी तक एक मौत हो चुकी है जबकि जयपुर में 13 मरीज भर्ती है, जिनका उपचार चल रहा है।

स्वास्थ्य अधिकारियों ने संक्रमण की रोकथाम के लिए निगरानी बढ़ाने और अस्पतालों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। विशेषज्ञों ने बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है।

रबी के सीजन में किया बिजली का समुचित प्रबंधन : हीरालाल नागर

- 'गर्मी में भी नहीं आने देंगे कोई कमी'

जयपुर। ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में सरप्लस स्टेट बनाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने रबी के सीजन में समुचित प्रबंधन कर प्रदेश में बिजली की कोई कमी नहीं आने दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि गर्मी के इस मौसम में भी उत्पादन, प्रसारण, वितरण सहित सभी विद्युत निगमों के अधिकारी पूर्ण समन्वय के साथ कार्य कर उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे।

ऊर्जा राज्यमंत्री हीरालाल नागर ने गुरूवार को विद्युत भवन में ऊर्जा विभाग की समीक्षा की।

नागर गुरूवार को विद्युत भवन में ऊर्जा विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आरडीएसएस, स्मार्ट मीटरिंग, पीएम-कुसुम मुफ्त बिजली जैसी योजनाओं में गति को बढ़ाएं। जहां अधिक विद्युत छीजत हो, वहां विद्युत तंत्र को सुदृढ़ करने, फीडर पृथक्कीकरण के साथ ही सतर्कता अभियान चलाकर बिजली चोरी को प्रभावी रूप से रोका जाए। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रदेश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के साथ एमओयू किए गए हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि इन एमओयू को चरणबद्ध रूप से यथाशीघ्र क्रियान्वित किया जाए ताकि प्रदेश की भावी ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सके।

नागर ने इस दौरान राज्य सरकार द्वारा बजट में घोषित ग्रिड सब स्टेशनों के निर्माण कार्य की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि जीएसएस निर्माण में भूमि चयन सहित अन्य आवश्यक प्रक्रियाएं जल्द पूरी कर कार्यों की गति और बढ़ाएं ताकि प्रदेश में प्रसारण तंत्र को और मजबूत किया जा सके। बैठक के दौरान ऊर्जा विकास निगम के प्रबंध निदेशक ओम कसेरा ने बताया कि राज्य में पावर सप्लाई की व्यवस्था सामान्य है। मई और जून के माह में हीटवेव की चेतावनी को देखते हुए विद्युत मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त इंतजाम पहले से ही कर लिए गए हैं। विद्युत की पर्याप्त उपलब्धता के कारण कहीं कोई कटौती नहीं की जा रही है।

प्रसारण निगम के प्रबंध निदेशक नथमल डिडेल ने बताया कि प्रभावी मॉनीटरिंग के माध्यम से ग्रिड सब स्टेशनों के निर्माण कार्यों को मिशन मोड पर पूरा किया जा रहा है। बीते करीब डेढ़ साल में प्रदेश में 400 केवी, 220 केवी तथा 132 केवी के कुल 30 ग्रिड सब स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त 133 ग्रिड सब स्टेशनों के काम मौके पर चल रहे हैं। जिन्हें निर्धारित समयावधि में पूरा किए जाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।

उत्पादन निगम के सीएमडी देवेन्द्र श्रृंगी ने बताया कि 11 विभिन्न केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के साथ अक्षय ऊर्जा एवं तापीय ऊर्जा की परियोजनाओं के लिए एमओयू किए गए हैं। जिनमें से एनटीपीसी, कोल इंडिया तथा एनएलसी के साथ परियोजनाओं पर संयुक्त उद्यम समझौते निष्पादित किए जा चुके हैं तथा कंपनी गठन का कार्य प्रगति पर है। एनजीईएल के साथ एनटीपीसी राजस्थान ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी का गठन किया जा चुका है। यह कंपनी रिन्यूबल एनर्जी के क्षेत्र में 25 गीगावाट क्षमता की स्थापना के लिए 1 लाख करोड़ का निवेश करेगी। जोधपुर एवं अजमेर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जुड़े।

बावड़ियों के संरक्षण के लिये विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश

जयपुर। राजस्थान की प्राचीन विरासत और जल संरचनाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली बावड़ियों के संरक्षण एवं संवर्द्धन को लेकर राज्य सरकार ने ठोस पहल शुरू कर दी है। उपमुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप राजस्थान की बावड़ियों का संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री ने पर्यटन विभाग एवं पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि बावड़ियों के संरक्षण हेतु एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर शीघ्र प्रस्तुत करें। इस कार्ययोजना में बावड़ियों के पुनरुद्धार, पानी के प्रवाह मार्गों की मरम्मत, डिसिल्टिंग और कचरा निस्तारण जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया जाएगा। गुरुवार को शासन सचिवालय स्थित उपमुख्यमंत्री कार्यालय के सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य की बावड़ियों को पूर्ण रूप से संचालन में लाने हेतु सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं।

शेखावाटी की हवेलियों के संरक्षण के लिए बायलॉज में परिवर्तन के निर्देश

जयपुर। उपमुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने शेखावाटी क्षेत्र की ऐतिहासिक हवेलियों के संरक्षण एवं जीर्णोद्धार को लेकर गुरुवार को शासन सचिवालय स्थित उपमुख्यमंत्री कार्यालय के सभागार में एक अहम बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि आवश्यक हो तो बायलॉज में बदलाव कर हवेलियों के संरक्षण और पुनर्निर्माण को प्रोत्साहन दिया जाए। उन्होंने इस दिशा में सभी संबंधित विभागों को समन्वय के साथ ठोस कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए।

बैठक में प्रमुख शासन सचिव स्वायत्त शासन राजेश कुमार यादव, पर्यटन विभाग के अतिरिक्त निदेशक आनंद त्रिपाठी, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग निदेशक पंकज धरेन्द्र, तथा पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक (विकास) राजेश शर्मा उपस्थित रहे। इसके अलावा झुंझुनू, चूरू और सीकर के जिला कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। बैठक में इस क्षेत्र में कार्यरत विषय विशेषज्ञों ने भी वर्चुअल रूप से भाग लिया।